nwda.gov.in

गंगा डाल्फिन के लिए एंबुलेंस सेवा पर मुहर

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने डाल्फिन के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया
- कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव के लिए उत्तर प्रदेश को मिलेगी मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गंगा डाल्फिन के संरक्षण के लिए एक नए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की राष्ट्रीय परिषद ने गत दिवस हुई बैठक में संकटग्रस्त डाल्फिन की जान बचाने के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू करने की योजना पर मुहर लगा दी। डाल्फिन एंबुलेंस एक विशेष प्रकार का वाहन है, जो संकटग्रस्त डाल्फिन की मदद करेगा। गंगा के प्रवाह वाले राज्यों को ये एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी।

डाल्फिन कई कारण से तट पर आ जाती हैं और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। इन कारणों में पानी के स्तर में कमी, उसकी गुणवत्ता में कमी, शिकार की कोशिश या फिर उनके लिए अनुकूल वातावरण का अभाव प्रमुख है। ऐसी डाल्फिन की सहायता के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है, जो कि संकटग्रस्त डाल्फिन की पहचान करने के साथ ही उनकी सहायता और फिर उन्हें जल में छोड़ने का काम करेंगी। ये वाहन नौका के रूप में होंगे और उनमें उपचार के साधन मौजूद होंगे। एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फार द प्रोटेक्शन आफ गंगा डाल्फिन नाम से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत डाल्फिन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। एनएमसीजी ने पिछले साल गंगा में जैव विविधता की समीक्षा के बाद डाल्फिन की संख्या बढ़कर चार हजार तक पहुंचने का दावा किया था। एनएमसीजी के अनुसार, प्रदूषण में कमी और डाल्फिन के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के कारण उनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ साल पहले उनका अस्तित्व समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो रही है।

एनएमसीजी की नई परियोजना गंगा की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके दायरे में कछुओं को भी लिया गया, जिनकी कुछ प्रजातियां विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। कछुओं के संरक्षण का प्रोजेक्ट केवल उत्तर प्रदेश में चलना है। इस परियोजना के तहत कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों का न केवल पुनर्वास किया जाएगा, बल्कि गंभीर खतरे से घिरीं कम से कम तीन प्रजातियों को फिर से जीवन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना की निगरानी के लिए एक विशेष केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।

बंगाल में एसटीपी स्थापना में धन की बाधा दूर : इस बीच गंगा नदी को साफ-स्वच्छ बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बंगाल में नए संयंत्र की स्थापना की राह भी साफ हो गई है। यह इंटीग्रेटेड सेप्टेज प्लांट बंगाल के बर्धमान में स्थापित किया जाना था, लेकिन पैसों को लेकर अड़चन आ रही थी। पहले इसके लिए छह करोड़ रुपये से कुछ अधिक धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन इससे जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। अब 10.35 करोड़ रुपये में 50 किलोलीटर प्रतिदिन जल क्षमता वाला ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। समस्या यह थी कि पहले जो प्लांट लगाया जा रहा था, उसमें रखरखाव के खर्चे शामिल नहीं थे। अब जो संयंत्र मंजूर किया गया है, उसमें प्लांट के 10 साल के रखरखाव और मरम्मत की सेवाएं भी शामिल हैं।